(b) if so, whether Indian side have entered into any agreement with the Chinese side to reduce troops along the Eastern borders so far which would help India to manage the insurgency situation in the North-East better and thereby upset Pakistan's designs|rhythm in using the ISI to create instability in that region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) Yes, Sir.

(b) The Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquillity Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas, signed on 7th November, 1993, provides, *inter-alia*, that the two countries will reduce their military forces along the line of actual control. The extent depth, timing and nature of reduction of forces are being discussed in the India-China Joint Working Group and the Expert Group. Discussions on this subject were continued during the third meeting of the Expert Group, held in New Delhi from 2nd to 4th March, 1995. The implementation of the understanding on force reduction will help in maintaining peace and tranquillity in the India-China border areas.

Setting up Nuclear verification facility by the USA in India

3612. SHRI K. R. MALKANI:
SHRI SOM PAL:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that U.S.A. has persuaded India to allow a verification facility installed on our territory to monitor any nuclear testing by India as reported in the Indian Express dated the 12th February, 1995;

(b) whether it amounts to indirect commitment to NET, even without signing it; and

(c) whether this is a reversal of our national policy to keep our nuclear options open?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) No, Sir. However, the Indian seismic monitoring facility known as the Gauribidarur Array (GBA) in Karnataka has participated in international trial tests undertaken by the Group of Scientific Experts (GSE) as part of an exercise by the Conference on Disarmament at Geneva to evolve a verification system for a future Comprehensive Test Ban Treaty CTBT. It is universially accepted that an international seismic monitoring network is essential to verify a CTBT. The third technical test (GSTT-3) exercise to be carried our in 1995, will involve the participation of around 48 seismic station located in more that 25 countries. The GBA will also be participating in GSETT-3.

(c) Does not arise.

मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिये खाद्य प्रसंस्करण परियोजनायें

3613. **श्री अजीत जोगी :**
श्री एस.एस. सुरजेवाला:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत की गई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) श्रम दिवसों के अनुसार इन परियोजनाओं की रोजगार सृजन क्षमता कितनी है ; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की निर्यात क्षमता कितनी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) एल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन और लघु उद्योग के लिये आरक्षित मदों तथा चीनी को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के

लिये किस औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती । बहरहाल, इस प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, विदेशी सहयोग आदि के लिये मंजूरियां दी गई हैं। 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे 7-7 प्रस्तावों को मंजरी दी गई है । कार्यान्वित होने पर मध्य प्रदेश में इन यूनिटों में 1317 व्यक्तियों को और उत्तर प्रदेश में 870 व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। अनुमान है कि 5 वर्ष की अवधि में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से क्रमश: लगभग 1292 करोड़ रुपये और 650 करोड़ रु० का निर्यात किया जायेगा ।

Raising the capital investment, in Ice-cream manufacture industry

3614. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is being considered to raise the quantum of basic capital investment in the Ice-cream manufacturing industries of the country;

(b) if so, what is the proposed quantum of maximum capital investment in case of each of the industrial units:

(c) whether it has also been proposed to give exemption to such Ice cream manufacturers whose capital investment is to be raised to sell upto 50 per cent of their total production in the domestic market;

(d) if so, whether Government propose to announce some incentives for the protection of industrial units presently engaged in the Ice-cream Manufacturing, with small capital investment; and

(e) if so, what are the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (e) Manufacture of ice cream is reserved for exclusive development in the small scale sector. As per the policy invogue the investment limit for ice cream industry is Rs. 60 lakhs i.e. the investment limit for SSI unit. As per the current policy there is no change in the investment limit for ice cream industry in the small scale sector.

आइसक्रीम उद्योग में पूंजी निवेश

3615. श्री मती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आइसक्रीम निर्माण के लिये वर्तमान पजी निवश की सीमा को बढ़ा कर 5 करोड़ रुपये कर देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं की स्थापना होगी;

(ग) यदि हां, तो इन बड़ी परियोजनाओं द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग कर कुल कितनी मात्रा में वार्षिक उत्पादन किये जाने की संभावना है और आइसक्रीम के उत्पादन के लिये एक परियोजना के मामले में कुल कितनी मात्रा में कच्चे दूध की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि चालू वर्ष तथा गत वर्षों के दौरान देश में आइसक्रीम के निर्माण में कुल दूध के उत्पादन में से औसतन कितने प्रतिशत दूध वार्षिक उपयोग किया जाता रहा है, यदि हां, तो यह मात्रा कितनी है ; और

(ङ) इस संबंध में तथ्य क्या हैं और क्या सरकार द्वारा आइसक्रीम निर्माण के क्षेत्र में बड़ी अतिरिक्त परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति देने के कारण देश में दूध की कमी होने तथा उसकी कीमतें बढ़ने के बारे में कोई अनुमान लगाया गया हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?